



भारत में आधुनिकता और वैश्विकरण

श्री वाडसीभाई चौधरी
जी. डी. हाईस्कूल, विसनगर

सामाजिक विज्ञानों और खासकर समाजशास्त्र में आधुनिकता के बारे में कई विद्वानों ने अपने विचार रखे कई सिद्धांत भी रचे फिरभी बार बार प्रश्न यह उठता है कि आखिर आधुनिकता कब तक । आधुनिकता के बारे में बहुत ज्यादा बहस मोर्डनिटी को लेकर जगह जगह गोष्ठियों, परिगोष्ठियों में बहुत हुई और होती रहेगी । कई सारे अभ्यासी भी अपने अपने अभ्यासों में इस बात की जाँच करने में झुटे है । आखिर टडिशन क्या है, मोर्डनिटी क्या है, कैसे दोनों को मिलाया जाए? क्या आदमी अपने आप आधुनिक रहता है, या कि यह परिस्थितियों का दबाव है जो उसे आधुनिक बनाता है ? यदि वह सचमुच पुरे तौर से जागरूक है तो क्या उतनी जागरूकता आधुनिकता के लिए काफी है , या इसके अलावा भी कुछ चाहिए - जैसे कई सारे सवाल मौजूद है । आज आम आदमी भी मोर्डनिटी चाहता है । जो या तो किसी दुसरे को देखकर अपने आप में सुखी है या फिर टेलीविजन विज्ञापनों को देखकर, पढकर, सुनकर दंभ को अपनाया हुआ है । साठोत्तर युग में आधुनिकतावाद की चर्चा करीब करीब समाप्त हो चुकी थी, किन्तु आधुनिकता की चर्चा ने अपना नया रूप धारण कर नई गति पकड ली है ।

प्रवर्तमान में उत्तर आधुनिक शब्द का प्रचलन बढा है , जिसमें मनुष्य और समाज दोनों को अलग अलग रूप में देखा जाने लगा है । एन्थेनी गिडेन्स एक ब्रिटिश समाजशास्त्री जो कि आधुनिकता के मूर्धन्य विद्वान माने जाते है । वे सोचते है कि पिछले तीस चालीस वर्षों में हमारे अस्तित्व को ईस आधुनिकता ने झकझोर दिया है । हमारी सुरक्षा की संपुर्ण भावना तिरोहित को गई है । इस अनिश्चितता ने हमारी पहचान को धूधला कर दिया है । संस्थाओं के प्रति अब हमारी कोइ आस्था नही थीं जो कुछ आस्था है वह बहुत कमजोर है आदमी अगर अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है तो उसे तार्किक सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए । आज से पचास साठ पहले हमारे देश में एक आदिवासी के सामने उभरे पहचान की कोइ समस्या नही थी । उसके लिए सब कुछ पूर्व निश्चित था । उसे जंगल में रहना था । केवल खरिफ की फसल लेना था आर पढाई लिखाई तथा नौकरी घंटों से उसे कोइ ताल्लुक नही था । आज इस आदिवासी के सामने सैकडो समस्याए है । वह आधुनिकता के चौखट पर खडा है और कैरियर के रास्ते उसे चुनौतियाँ दे रही है । अब वर्तमान में उसकी क्या पहचान है ।

आज मनुष्य वैश्विक बनने के प्रयास में समाज और मानवीयता को भुलता जा रहा है । इन दोनों पहलुओं से दूरी बनाता जा रहा है । उसके लिए आज अपना परिवार, राष्ट्र और समाज कोई माईने नही रखता । वैश्विकरण और खासकर पश्चिमीकरण से भारतीय समाज व्यवस्था पर अच्छा खासा प्रभाव पडा है । अमरिका, युरोपीय देशों की समाजव्यवस्था के मानदण्ड, मल्यों का प्रभाव हम भारतवर्ष के लोगों पर बखुबी देख सकते ह, प्रतिदीन ईसकी गति भी बढती जा रही है हमारी सारी सामाजिक संस्थाए जैसे

परिवार, धर्म विवाह, आर्थिक संस्था, राजनैतिक संस्था एवं शिक्षा संस्था पर भी इसका प्रभाव बरकरार है। बुनियादी रूप से उपर्युक्त संस्थाओं का ढाँचा बदल सा गया है। फिर भी एक आम आदमी आधुनिकता को अपनाने को बेताब है। वैश्विकरण की बलिहारी से आज की परिवर्तनशील मानसीकता वाले समाज में हम एक प्रक्रिया को उदारीकरण या भूमंडलिकरण नामों से बुलाने का दोहरापन सिखते जा रहे हैं। भारतीय एवं कृषि आश्रित उद्योगों पर इस प्रावधान का क्या असर पड़ेगा, इसे सहज ही समजा जा सकता है। हमारे देश के औसत कृषक या ग्रामवासी के लिए आज भी उसका परिवेश, उसके इर्द गिर्द के पशुप्राणी और पैड पौधे, प्रकृति के तब आदि उसके जिवन क अभिन्न अंग है। यह पैड पौधे उसे धरेलु इस्तेमाल के साधन और उपचार के सस्ते और सुलभ नुस्खे प्रदान करते हैं। किन्तु आज जिस तरह व्यक्ति दूरसंचार माध्यमों के झुठे और भ्रमझाल फैलानेवाले विज्ञापनों के चलते अपनी सही पहचान खो रहा है, वह अपने जीवन में नयेपन को ढूँढता है और पुरानेपन को भूलने में पडा है। हमारे लिए हिटलरशाही राजनीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भरमार, विदेशों का दबाव, आतंकवाद और देश में चल रहे आंदोलन देश को मजबुर किए हुए हैं, ऐसे में उत्तर आधुनिक समाज कई सारी परेशानियाँ और सवाल लिए खडा है।

देश में चल रहे आर्थिक सुधार की नीतियाँ, साँस्कृतिक पुनरुत्थान, उदारीकरण आदि कुछ ऐसे शब्द हैं। जो विश्व के मानव जीवन के आर्थिक जीवन में बार बार प्रयुक्त होते हैं, इन शब्दों से लगातार अहसास दिलाया जाता है कि वैश्विकरण एक आवश्यक आर्थिक प्रक्रिया है, जिसके बगैर इक्किसवीं सदी में मानवजाति का कल्याण सम्भव नहीं। जातिप्रथा, धर्म और राष्ट्र के जटिल बन्धनों में कैद, सोचने - समझनेवाले गरीब, मध्यवर्गिय व्यक्ति को यह बात उचित और तर्कसंगत भी लगती है। पुँजी के निर्माण की प्रक्रिया में पहला और अधिकांश फायदा प्रारंभिक पुँजी लगानेवाले को होगा, फिर कुछ हद तक कय क्षमता रखनेवाला उपभोक्ता लाभान्वित होगा और अंत में कय क्षमताविहिन गरीब आदमी फटी फटी आखों से इस प्रक्रिया को देखता रह जायेगा। उसके भाग्य में लाभान्वित होना मुनासिब ही नहीं है इतना ही नहीं वह विज्ञापन की भ्रमझाल में फंसकर पैसे को भी खर्च कर देता है। आज पुँजिवादी भूमंडलिकरण का नेतृत्व पश्चिम के दश कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अविकसीत और विकासमान देशों की प्राकृतिक संपदा, श्रमशक्ति, बौद्धिक संपदा, वित्तीय पुँजी, बाजार और परमाणु शक्ति समेत उर्जा का इस्तेमाल वहराष्ट्रीय कंपनियाँ और अन्य प्रकार की व्यापारिक कंपनियाँ के पक्ष में करना है। जो देश इस भूमंडलिकरण के सामने नतमस्तक हो गए हैं वे तो ठिक हैं, जो ऐसा करने में कतराते हैं या इनकार करते हैं, वहाँ अमरिकी हितों का पोषण करनेवाली तानाशाही कायम करने की साजिस की गई है। आज विश्व के अधिकतर देशों में इस परिस्थिति का निर्माण हुआ, जिनमें इन्डोनेशिया, मिश्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, चिली, पेरू, बर्मा आदि देशों का नामोल्लेख किया जा सकता है। भूमंडलिकरण के इस दौर में जनतंत्र को कुचलने और नए नए प्रकार की तानाशाही थोपने की या पुँजी के स्वार्थों का पोषण करती है। भूमंडलिकरण की डोर आज की महाशक्ति के हाथ में है और वह जो करकरा रही है वह जनतंत्र विरोधी सरकारें करती है। स्वतंत्र देश को भी आज आत्म निर्णय के अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है। बीमा क्षेत्र में विदेशी पुँजी निवेश को छूट, बाजार, संसाधन और

विनीय संपदा के इस्तेमाल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल के आयात को लेकर मुक्त कर देना, सब्सिडी कम करने से चिजों के दामों में बढ़ावा देना जनविरोधी आर्थिक नीतियाँ हैं।

वैश्विकरण के नाम पर इस दुनिया में प्रादेशिक खेमाबन्धि या ग्लोबल कार्टेलाइजेशन कहना अधिक उपयुक्त होगा। वैश्विकरण के दौर में कम्पटीशन ही विकास का गुरुमंत्र है। वैश्विकरण या कि प्रादेशिक खेमाबन्धि के परिणाम स्वरूप बहुभाषी, बहुप्रादेशिक एवं बहुराष्ट्रीय परिवेशों में काम करनेवाले लोग सवाल करने लगे हैं कि इस सारी गहमागहमी में आखिर उनकी जड़ कहा है। यूरोप के आर्थिक एकीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि वहाँ गैर यूरोपीय देशों द्वारा हो रहे आयात पर अंकुश लगाया जाए। अमरिकी संगठन और सार्क भी अपने अपने ढंग से यही काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज हो जाएगा। जहाँ मनुष्य एवं उनके द्वारा संचालित समाज का स्थान टुंडना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इस का कारण आज सारी दुनियाँ में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो तो दिखाई दे रहा है, उसका एक तिहाई हिस्सा बहु राष्ट्रीय कंपनियों का आंतरिक लेन देन मात्र है। जबकि दुसरा एक तिहाई हिस्सा गिनी चुनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बिच सौदों से बना है और सिर्फ वचे हुए एक तिहाई हिस्से को वास्तव में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सजा दी जा सकती है।

वैश्विकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया पिछले दो तीन दसकों से दुनिया के तमाम विकाशशील देशों में अलग अलग पैमानों पर कार्यान्वित होती जा रही है। देश के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिधि के भितर लाने के लिए कुछ आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। वैश्विकरण यानी कि विश्व का व्यापारीकरण एक हद तक इस दुनियाँ की विकासशील जनसंख्या को बहुराष्ट्रीय व्यापारिक शक्तियों का मोहताज बनाता जा रहा है।

विज्ञान एवं टेक्नोलोजी पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यह भयानक एकाधिकार अब वैश्विकरण के माहौल में सचमुच विश्वव्यापी और ग्लोबल होता जा रहा है। सवाल उठता है कि टेक्नोलोजी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूलभूत सामाजिक किरदार को इस दुनिया की व्यवस्थाएँ कितनी प्राथमिकताएँ दे रही हैं? आज भारतीय समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में नवाचार एवं बदलाव हमें सूचित करते हैं कि आने वाला वक्त इन तत्वों को बदलने में और भी अधिक रोचकता प्रदान करेगा। बदलाव का यह दौर भारत के नागरीकों को नई चुनौतियाँ भी दे रहा है, क्या लोग इन बदलाव सहन करने को शक्तिमान हैं या आधुनिकता की आड़ में समाज में विपरीत स्थितियाँ भी पैदा हो रही हैं तो उनका समाधान जाचने का प्रयास भी होना लाजमी है। आज भी भारतीय समाज की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी से त्रस्त है और एक झूट रोटी के लिए दरबंद की ठोकरे खाने को बेबस है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि आधुनिकता को हमारी प्राचिन और समृद्ध संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। फिर भी वह अनचाहे ही आधुनिकता को अपना लेते हैं आज नौबत ऐसी आयी है कि इन सारी समस्याओं का समाधान हमें भारतीय नागरीक बनकर खोजना होगा तब ही कुछ बात बन सकती है। हमारे नीति निर्धारक और जनप्रतिनिधीओं को भी अपनी सोच समाजोत्थान की और झुकानी होगी तब ही आधुनिकता के कुप्रभाव से युवा और समाज को एक नवनिर्मित राष्ट्र की कमान आर सुनहरे भविष्य का खाब दे सकते हैं।